

सम्पादकीय

नए अवसरों के द्वारा
खोलने वाला समय,
२०२५ में भारतीय
अर्थव्यवस्था को
मिलेगी मजबूती

भू-राजनीतिक चुनौतियों से उत्पन्न आपूर्ति शृंखला और कच्चे तेल के दामों में आई तेजी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रही है। तकनीकी प्रगति, प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत जैसे नीतिगत उपायों से भारत वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत रखने में सफल रहा है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी निवेश के रिकार्ड प्रगाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इंजन का कार्य किया है तो बढ़ती मुद्रास्फीति, घटता उपभोग, वित्तीय ऋण और जीडीपी वृद्धि पूर्वनुपानों में कमी ने बड़ी चिंताएं भी पैदा की हैं। 2047 तक भारत को विकासित राष्ट्र का दर्जा दिलाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थितियों में वर्ष 2025 की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। निवेश, उपभोग और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सुधार वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार तैयार करेंगे। दुनिया में सबसे अधिक आवादी वाला देश होने के कारण वर्ष 2025 में भी घरेलू मांग में मजबूत निरंतरता बनी रहेगी। शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की मांग में भी सकारात्मक रुझान दिखाई दे रहा है। जून 2024 में भारत की जीडीपी में निजी अंतिम उपभोग व्यय 57.9 प्रतिशत से बढ़कर 60.4 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की दिशा में बढ़ना होगा। नीति निर्माताओं को निवेश में विविधता लाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी तक निवेश स्टील, मशीनरी, केमिकल्स जैसे भारी उद्योगों में ही अधिक रहा है। विविध उद्योगों को बढ़ाव मिलने से घरेलू मांग में भी तेजी से वृद्धि होगी। नगाचार संस्कृति, अकादमिक-उद्योग साझेदारी और वैश्विक बाजार पहुंच का विस्तार करके भारत 2025 में स्वयं को वैश्विक नवाचार पारव हाउस में बदल सकता है। वर्ष 2024 में सेंसेक्स और निपटी के रिकार्ड ऊँचाई पर पहुंचने से भारत का वित्तीय बाजार वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। यह तेजी 2025 में भी बढ़ी रह सकती है, इसके लिए विदेशी मुद्रा बाजार में स्थायित्व पर काम करते हुए अपनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने पर अधिक काम करना पड़ेगा। साथ ही निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए राजकोपीय अनुशासन पर विशेष ध्यान देना होगा। वर्ष 2025 में सरकार की प्राथमिकता मौद्रिक नीति में मामूली ढील द्वारा मुद्रास्फीति के दबाव को घटाने की भी होगी। पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलने से निम्न एवं मध्य आय वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। जन धन, आधार और मोबाइल के तहत खोले गए खातों में 2.32 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जमा है। वर्तमान में ई-लेनदेन बढ़कर 134 अरब रुपये हो गया है, जो सभी वैश्विक डिजिटल भुगतानों के 46 प्रतिशत



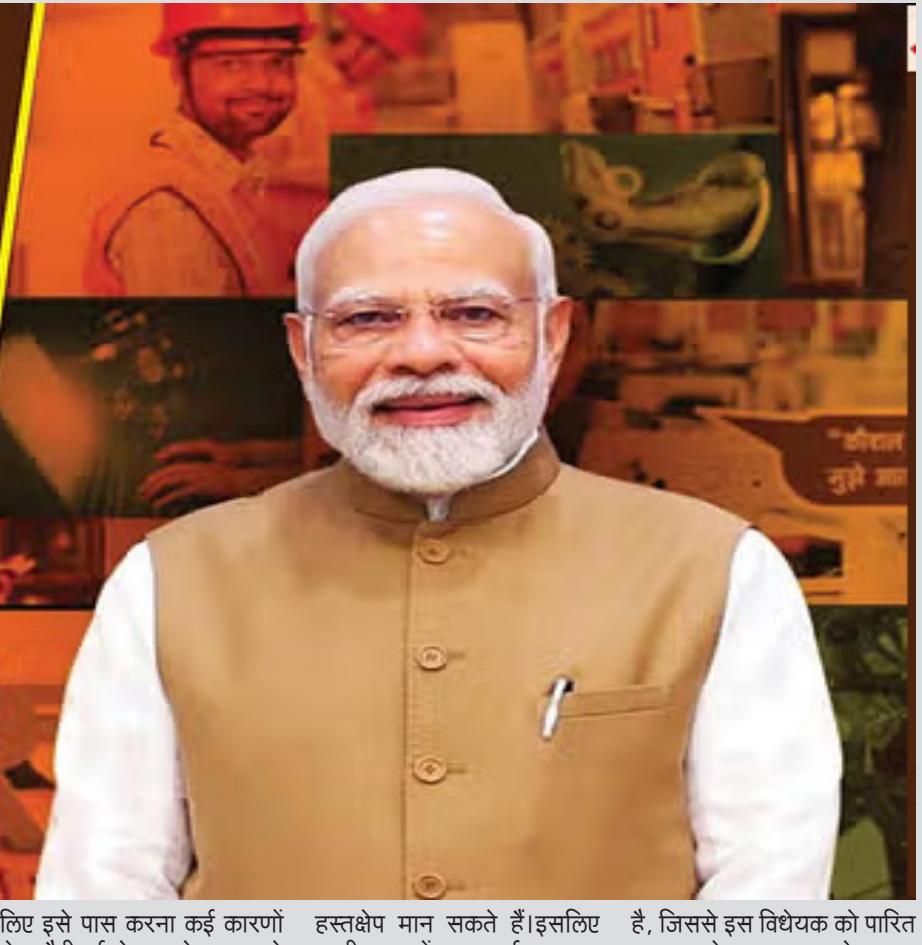
की मांग 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 6.2 प्रतिशत हो गई। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार मासिक प्रति व्यक्ति व्यय में शहरी-ग्रामीण अंतर वित्त वर्ष 2011-12 में 84 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 71 प्रतिशत हो गया। यह 2023-24 में और घटकर 70 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग वृद्धि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में असमानता कम हुई है। चालू वित्त वर्ष की टूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में आम चुनावों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पहली तिमाही की 6.7 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले थीमी है। तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था पुनः बढ़ने का अनुमान है। क्रिसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से सात प्रतिशत के बीच रह सकती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत के पास अभी कार्यशील युवाओं की सबसे बड़ी फौज है। 25 से 54 आयु वर्ग की महिलाओं के बीच श्रम बल भागीदारी दर में भी वृद्धि हुई है। हालांकि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और मेक इन इंडिय अभियान सहित अनेक सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र अपेक्षित लाभ लेने में सफल नहीं रहा है। इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रकृति पर अधिक

मोदी सरकार के राजनीतिक कौशल की परीक्षा का साल होगा 2025

मोदी सरकार ने एक दशा एक चुनाव का बिल संसद में पेश तो कर दिया, लेकिन एक साथ चुनाव करना इतना आसान नहीं है। यह उम्मीद है कि यह बिल अप्रैल मुहुरा है। इस लागू करने के लिए संविधान में संशोधन और व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। मोदी सरकार के

के कंद्राकरण और सघवाद के लिए
खतरा मानते हैं। क्षेत्रीय दल,
जिनकी राजनीति राज्य स्तर पर
केंद्रित है, इसे 3पने अधिकारों में
समावेश
इसे बताते हैं।
राज्य स्तर पर

क्षा के लिए भजा गया है। विपक्ष
अल्पसंख्यक विरोधी नीति
एकर मुद्दा बना रहा है।
प्रसभा में एनडीए के पास बहुमत



आर असताष के दार स भा गुजर सकता है। पक्ष विपक्ष के बीच प्रतिद्वन्द्विता दुश्मनी का रूप लेती जा रही है। मोदी सरकार, जो 2024 में चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी है, को न केवल अपने एजेंडे को लागू करने की चुनौती होगी, बल्कि विपक्ष और जनता की अपेक्षाओं के बीच संतुलन भी साधना होगा। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव का बिल संसद में पेश तो कर दिया, लेकिन एक साथ चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। यह विचार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद स चुनौतापूर्ण होगा। इस लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, और 356 में संशोधन करना पड़ेगा सरकार की इस पहल को लेकर कानूनी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इस पर अदालतों में याचिकाएं दायर हो सकती हैं। न्यायपालिका का दृष्टिकोण भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होगा। इसके लिये संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक है। जबकि विपक्षी दल इसे सत्ता

एनडाए घटकों का समर्थन जुटाना ही चुनौतीपूर्ण होगा। मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि राज्यों की विधायिकाओं का कार्यकाल छोटा या बड़ा करना। यही नहीं पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए भारी संख्या में ईवीएम और वीरीपैट मशीनों की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के लिए इसे संभालना कठिन हो सकता है। वक्फ बोर्ड के बिल को पास कराना भी एक चुनौती वर्तमान में, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) के पास

ना अपेक्षाकृत सरल हा सकता हालांकि, विधे यक की दनशीलता और विभिन्न नीतिक दलों के बीच मतभेदों रखते हुए, इसे पारित कराने में चुनौतियाँ आ सकती हैं। किंतु अपने मुस्लिम गोट बैंक को ने हुये सरकार को टिकाये रखने चन्द्र बाबू नायडू और नितीश कर, इस बिल को समर्थन देने से र सकते हैं। वैसे भी आगर यह पास कराना इतना आसान तो सरकार इसे जेपीसी को भेजती संसद की संयुक्तिं की पहली बैठक जल्द ही

का साल होगा 2025

हान का सभावना है, जो विधेयक की समीक्षा करेगी और आवश्यक संशोधनों पर विचार करेगी। इस प्रक्रिया के बाद, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कुल मिलाकर, तक (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित कराना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इसके लिए राजनीतिक सहमति और समर्थन जुटाना आवश्यक होगा। अम्बेडकर को लेकर विवाद से भी निपटना होगा संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉ. भीमराव आंबेडकर पर की गई टिप्पणी से उत्पन्न विवाद ने भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। विपक्ष इस बयान को आंबेडकर का अपमान बताते हुए गृह मंत्री से माफी और इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा को धेरने के लिये दिल्ली में डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान और उनके विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जबकि, कांग्रेस जनवरी पहले सप्ताह हो से ही अम्बेडकर को लेकर सरकार के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। डॉ. आंबेडकर दलित समुदाय के प्रतीक हैं। उन पर की गई किसी भी नकारात्मक टिप्पणी से इस समुदाय में असंतोष बढ़ सकता है, जिससे भाजपा को आगामी चुनावों में नुकसान हो सकता है। दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों की चुनौती 2025 में भारत के दो प्रमुख राज्यों, दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इन चुनावों के परिणाम न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे, जिससे मोदी सरकार की आगामी नीतियों और रणनीतियों की दिशा निर्धारित होगी। दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के लिए चुनाव फरवरी 2025 में संभावित है। वर्तमान में, आम आदमी पार्टी सत्ता में है और मुख्यमंत्री आतिशी मालेना है। कांग्रेस ने अब तक 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। वर्तमान में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव नये साल मोदी सरकार को विपक्ष से कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो राजनीतिक आर्थिक, और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होंगी। सबसे पहले विपक्ष का विरोध एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर झेलना होगा जिसके विपक्ष इसे संघटना के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों को कमज़ोर करने का आरोप लगा सकता है। विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस, अडानी समूह से जुड़े विवादों को लेकर सरकार की पारदर्शिता और कॉर्पोरेट कनेक्शन पर सवाल उठाता रहेगा। विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को धेरने की कोशिश करेगा। मणिपुर जैसी जगहों पर हुई हिंसा और सामाजिक असंतोष को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहेगा। ये मुद्दे सरकार की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। विपक्ष सामाजिक न्याय और आरक्षण के विषयों के आक्रामक रूप से उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर सकता है। विशेष रूप से दलित और पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा। विपक्ष चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर सरकार की विदेश नीति पर हमला बोल सकता है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के संदर्भ में।

पारास्थितिका क शल्पकार ह भारताय हाथी, आखिर क्यों है इतने खास

घास के मैदानों में पाया जाने वाला यह शाकाहारी विशालकाय जीव एक दिन में करीब 200 किलोग्राम तक भोजन करता है और 100 लीटर पानी पीता है। इस भोजन में मुख्य रूप से घास, पत्तियां, फल, और टहनियां शामिल होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर कहे जाने वाले भारतीय हाथी न केवल आकर्षक जीव हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण के संतुलन में एक उत्कृष्ट और रक्षक हैं। यह प्रजातियों का संरक्षण भी सुनिश्चित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के घने वनों व घास के मैदानों में पाया जाने वाला यह शाकाहारी विशालकाय जीव एक दिन में करीब 200 किलोग्राम तक भोजन करता है और 100 लीटर पानी पीता है। इस भोजन में मुख्य रूप से घास, पत्तियां, फल, और टहनियां शामिल होती हैं। यह भोजन में मुख्य रूप से घास, पत्तियां, फल, और टहनियां शामिल होती हैं। यह भोजन प्रक्रिया केवल उनके जीवन को बनाए रखने के

रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। आजकल जंगलों की कठाई, खनन और शहरीकरण की वजह से हाथियों के प्राकृतिक-आवास का विखंडन तेजी से हो रहा है, जिससे हाथियों का दल व्याकुल हो जाता है और भोजन की तलाश में जुट जाता है। इसके कारण हाथियों को मानव बस्तियों के करीब आना पड़ता है, जिससे मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, भारत में उपर्याप्त ग्रामांश होने वाले जगहों की संख्या में 50% की गिरावट हुई है। प्राकृतिक-आवास की क्षति और विखंडन ने उनके सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया है, जिससे उनका आपसी संबंध कमज़ोर हो गया है और प्रजनन में भी कठिनाई हो रही है, इससे प्रजाति के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। भारत सरकार और अनेक संरक्षण संस्थाएं हाथियों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन आज के समय में हमें



महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय हाथी (एलीफस मैक्रिसमस इंडिकस) एशियाई हाथी की चार उपजातियों में से एक है, और यह मुख्यतः भारत में पाया जाता है। हाथी जंगलों में रहना पसंद करते हैं, पर खुले मैदानों और घास के क्षेत्रों में भी ब्रह्मण करते रहते हैं। ये स्वभाव से खानाबदोश होते हैं और एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरते। चलते-चलते ये हाथी वर्नों में बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिससे नए पेड़-पौधों का प्रसार होता है और जैव विविधता बनाए रखने में मदद मिलती है, अपने भारी पैरों से जमीन को दबाकर रास्ते बनाते हैं, जिससे छोटे जानवरों के लिए आवास उत्पन्न होते हैं और अन्य जीवों की आवाजाही में आसानी होती है, हाथी कई तरीकों से वृक्षों और वनस्पतियों की बढ़त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। इनकी महत्ता के कारण ही हाथी परिस्थितिकी तंत्र के लिए 'अमेरिका लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि उनके द्वारा छोड़े गए बीज जंगल में पुनः अंकुरित होते हैं, जिससे वृक्षों की संख्या बढ़ती है और वन का संतुलन बना रहता है। इनके मल में भी अनेक प्रकार के बीज होते हैं, जो मूदा की उर्वरता और जैव विविधता को बढ़ाते हैं। भारतीय संस्कृति व धार्मिक मान्यताओं में हाथी पूजनीय जीवों में से एक है, हाथियों को अति-पवित्र और शुभ माना जाता है, भगवान गणेश का स्वरूप हाथी के रूप में ही देखा जाता है, जो ज्ञान और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। धार्मिक-आस्था और पर्यावरणीय संरक्षण दोनों को जोड़ते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि हम हाथियों के संरक्षण के लिए प्रयास करें, ताकि हम अपनी सांस्कृतिक-धरोहर और जैविक विविधता को बनाए रख सकें। जब धरोहर की बात का संबंध हाथियों से हो और वत्सला का नाम ना आये, ऐसा नहीं हो सकता, पन्जा टाइगर रिजर्व की धरोहर बन चकी दिनिया की सबसे

प्रत्येक वर्ष कई व्यक्ति मानव-हाथी संघर्ष में अपनी जान गंवाते हैं और लाखों की फसल और संपत्ति का भी नुकसान होता है। इस संघर्ष के चलते प्रतिशोध में हाथियों की भी हत्या हो जाती है, इस दयनीय स्थिति ने हाथियों के संरक्षण को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। जबलंत मुद्दे की बात की जाये तो, जलवायु परिवर्तन भी हाथियों के लिए कठिनाइयाँ लेकर आया है, सूखे के कारण पानी की कमी हो रही है, जिससे हाथियों को पानी और भोजन की खोज में लंबी दूरी तय करना पड़ता है, बढ़ते तापमान और अनियमित मौसम चक्रों के चलते, ये चुनौतियाँ और भी गंभीर हो जाती हैं, इससे हाथियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उनकी जीवन-प्रत्याशा और प्रजनन-दर में भी गिरावट देखी जा रही है। आज हमारे भारत में दुनिया की 60% से अधिक एशियाई हाथियों की आबादी उष्णकटिबंधीय और रेष्ट्रिक्टिवीय तर्जों में स्थिरास कर्त्ती यह समझने की आवश्यकता है कि भारतीय हाथियों की सुरक्षा केवल सरकार या वन्यजीव संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है। हाथियों के संरक्षण में समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी भूमिका निभा सकता है, हाथियों के प्राकृतिक पर्यावास को बचाकर, हाथीदांत से बने सामानों के उपयोग को बंद कर, वन्यजीव गलियारे (कॉरिडार) में हाथियों के निर्बाध आवागमन को गति देकर, अधिकाधिक जागरूकता के माध्यम से भी आप इस प्यारे जीव की रक्षा कर सकते हैं, जो पूरे परिस्थितिक तंत्र के निर्माण में सहायक होगा। विश्व हाथी दिवस (12 अगस्त) जैसे विशेष दिन अवश्य मनायें, अन्य लोगों व होटे बच्चों को कहानियों के माध्यम से हाथियों के प्रति सजग करें, यह कदम निश्चित ही हाथियों के संरक्षण में सहायक होगा, क्योंकि हाथियों का संरक्षण केवल एक जीव के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परी, जैसे निश्चिता के संरक्षण का

हर नया साल, एक नई उम्मीद, नए संकल्प और नए अवसर

साल की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को पड़ती है और जश्न 1 जनवरी के शुरुआती घंटों तक जारी रहता है। हम नए साल की दहलीज पर खड़े हैं। हमारे लिए हर दिन नया है, हर साल नया है और हर नया साल एक नई उम्मीद, नया संकल्प और नये अवसर लेकर आता है। यह वह समय होता है जब हम अपने अंतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह न केवल समय की एक और परिभाषा है, बल्कि हमारे भीतर छुपे उन अनगिनत संभावनाओं और सपनों की शुरुआत भी है, जिन्हें हम अब साकार करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। नए साल की उन्हें भविष्य में आगे और साथ ही अंतीत में पीछे देखेने की अनुमति देते थे, ने 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन बनाया। हालांकि, 16वीं शताब्दी के मध्य तक इसे यूरोप में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। ईसाई धर्म की शुरुआत के बाद, 25 दिसंबर यौशु के जन्म का दिन, स्वीकार किया गया और 1 जनवरी नए साल की शुरुआत को विधर्मी मान गया। जब तक पोप प्रेगोरी ने जूलियन कैलेंडर को बदलकर 1 जनवरी को वर्ष की आधिकारिक शुरुआत नहीं कर दी तब तक इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा ऐसा माना जाता है



जो बहार द्वारा जनाने को प्रयत्न भी देता है। प्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को पड़ती है और जश्न 1 जनवरी के शुरुआती घंटों तक जारी रहता है। माना जाता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ और नाश्ते जो सौभाग्य लाते हैं, मौज-मस्ती करने वालों द्वारा खाए जाते हैं। दुनिया भर में लोग गीत गाने और आतिशबाजी देखने जैसे रीतिरिवाजों के साथ जश्न मनाते हैं। चूंकि नया साल अच्छे बदलाव का एक बड़ा अवसर है, इसलिए कई लोग आने वाले वर्ष के लिए अपने संकल्प लिखते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित प्रगोरियन कैलेंडर के इतिहास में जाए तो 1 जनवरी को पहली बार 45 ईसा पूर्व में नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया गया था। इससे पहले, रोमन कैलेंडर मार्च में शुरू होता था और 355 दिनों तक चलता था। सत्ता में आने के बाद रोमन तानाशाह जूलियस सीजर ने कैलेंडर बदल दिया। महीने के नाम

ADHUNIK TUTORIALS

" FOR THE STUDENTS, FROM A STUDENT "

FOR CLASSES 1st - 5th
(ADMISSION OPEN)

FACILITIES

- Air Conditioned & Well Furnished Classroom
- Water Cooler Available
- Hygienic Washrooms
- CCTV for Safety Purposes
- In Campus Parking



Dr. (Er) Puneet Arora (HON. DIRECTOR)
(B.Tech, M.Tech, MBA, Ph.D)

Awarded with 'Young Scientist & Best Teachers, Author of Many Books Chapters, Research Paper, Patent & Trademarks

Ms. Nilanjana Arora (Assistant Director)

- Ex. Student of Bethany Convent School, Bishop Johnson School & College, Girl's High School & College
- Pursuing B.Tech
- Awarded by TCS
- Certification in the Field of Web Development and Machine Learning .



Ms. Riya Arora (Counsellor)

- Ex. Student of Delhi Public School.
- Subject Topper of Delhi Public School
- Pursuing LLB from University of Allahabad .



Address: B-Block, ADA Colony, Mtek Campus, Naini, Prayagraj .

Contact :- Call and Whatsapp: 8542919234

आर डब्ल्यू ए का प्रतिनिधि मंडल कमिशनर से मिला

नेकी का डब्बा फाउंडेशन ने वीर बाल दिवस पर किया 7,000 कपड़ों का वितरण

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

नोएडा। गुरु गोविंद सिंह जी के चार वीर साहिबजादों - साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जारावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह - के अद्वितीय बलिदान और साहस को

में किया गया। 101 दिन चलेगा अभियान, 50,000 कपड़ों के वितरण का लक्ष्य फाउंडेशन के संस्थापक, गिरीश शुक्ला ने बताया कि यह अभियान 101 दिनों तक चलेगा, जिसके अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों में

से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें हर्षवर्धन मिश्रा, रजत अग्रवाल, कमल किशोर, वैभव तिवारी, ददन सिंह, परमानंद अग्रवाल, सचिन ठाकुर, सचिन सेंगर, उर्शी मसद, तेजपाल प्रजापति, भावना चौहान,

तथा

में

में</p

